CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 29 ▫ अंक- 174 ▫ रायपुर, शुक्रवार 17 जुलाई 2026 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

राशन दुकानों में बेचा जा रहा मसाला!

विधायक सुशांत शुक्ला के आरोप पर मंत्री बघेल ने की जांच कराने की घोषणा

रायपुर, 17 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुशांत शुक्ला ने राशन दुकानों के जरिए मसाला बेचने का आरोप लगाया. मंत्री दयाल दास बघेल के जानकारी नहीं होने बात कहने पर विधायक ने दस्तावेज हाथ में होने की बात कही. इस पर मंत्री बघेल ने दस्तावेज दिए जाने पर जांच कराने का आश्वासन दिलाया।

भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने अपने सवाल की शुरुआत राशन दुकानों के बचत स्टॉक के सत्यापन से की. उन्होंने आरोप लगाया कि जानकारी छिपाई जा रही है. अप्रैल 2025 तक की जानकारी दिए जाने की बात कहते हुए विधायक ने सवाल किया कि आखिर क्यों पूरी जानकारी छिपाई जा रही है? इस पर मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि हमने जांच कराई है. अधिकारी लगातार एक-एक दुकानों का जांच करते हैं. शिकायत सामने आने पर कार्यवाही भी की गई है।

इस पर विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि कौन-कौन से राशन आम जानों को उचित मूल्य के तहत दिया जाता है? उसका मेंटेनेंस कौन कर रहा है? मंत्री ने बताया कि अधिकारी हर 15 दिन में निरीक्षण करते रहते है. इस निरीक्षण भौतिक सत्यापन में जो शिकायत मिली है, उस पर कार्यवाही भी की गई है. राशन दुकान में चावल, शक्कर देते हैं. बस्तर में चना भी दिया जाता है।

विधायक अपना सवाल जारी रखते हुए पूछा कि क्या राशन दुकानों में मसालों की भी बिक्री की कोई व्यवस्था की गई है? मंत्री के इंकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि जानकारी इसलिए नहीं दी जा रही है, क्योंकि महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाओं पर दबाव बनाकर मसाला की बिक्री करवाई जा रही है. इसमें जांच की घोषणा कर दें. दस्तावेज मैं उपलब्ध करा दूंगा. मेरे हाथ में दस्तावेज है. इस पर मंत्री ने कहा कि जो भी दस्तावेज है आप दे दें, जांच करवा देंगे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र

महतारी वंदन योजना पर सदन में तीखी बहस, विपक्ष ने किया वॉकआउट

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन अब तक बेहद हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल के दौरान सरकार की महतारी वंदन योजना पर बवाल मच गया। विपक्ष ने इस योजना के लाभार्थियों की सूची से लाखों महिलाओं के नाम हटाए जाने को लेकर सरकार को चौतरफा घेरा। इसके बाद सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में आई इस बड़ी गिरावट को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार से जवाब मांगा। उनका आरोप था कि बिना किसी ठोस आधार के गरीब महिलाओं को इस लाभ से वंचित किया जा रहा है। इस दौरान सदन में काफी देर तक नारेबाजी होती रही, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस मामले पर सरकार की तरफ से पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि अपात्र पाई गई महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इसके अलावा कई लाभार्थियों की मृत्यु होने के कारण भी नामों को विलोपित करना पड़ा है। कुछ महिलाओं के आयकरदाता बनने और कइयों द्वारा जरूरी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराने को भी इसकी मुख्य वजह बताया गया। नतीजतन लाभार्थियों की कुल संख्या 70.09 लाख से घटकर अब 68.54 लाख पर पहुंच गई है। इस तरह कुल 1.55 लाख महिलाओं के नाम पात्रता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष सरकार के इस जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

प्रश्नकाल के दौरान सिर्फ महतारी वंदन ही नहीं, बल्कि राशन वितरण प्रणाली का मुद्दा भी जमकर गूंजा। विधायक शेषराज हरबंस ने गरीब परिवारों के हितों की बात सदन में उठाई।

डॉ. महंत का सरकार पर बड़ा हमला

विधानसभा में गरमाया माहौल 136 सप्ताह, 136 घोटाले

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए 136 सप्ताह के कार्यकाल में 136 घोटालों का आरोप लगाया है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और लोक निर्माण जैसे प्रमुख विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर होने का दावा किया है।

नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों का सीधा संबंध आम जनता की सुविधाओं और सरकारी सेवाओं से है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभागों में भ्रष्टाचार के दावों से प्रदेश के निवासियों में चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि इसका सीधा असर बुनियादी सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ता है। साथ ही, बिजली बिलों में बढ़ोतरी ने आम नागरिकों के बजट को पहले ही अस्त-व्यस्त कर दिया है।

डा. चरणदास महंत ने सदन में सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से प्रदेश की स्थिति बदहाल हो गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 136 सप्ताह के कार्यकाल में सरकार पर 136 बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। राजनीति

महंत ने बिजली बिलों में हुई भारी बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए कहा कि इसने राज्य की जनता की कमर तोड़कर रख दी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और लोक निर्माण विभाग में व्याप्त कथित अनियमिताओं को सरकार की नाकामी करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश की जनता इस वर्तमान शासन व्यवस्था से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। विधानसभा के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष के इन गंभीर आरोपों के बाद सरकार की ओर से क्या जवाब आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या विपक्ष इन आरोपों के समर्थन में सदन में दस्तावेज पेश करता है और सरकार इन पर किस तरह का स्पष्टीकरण देती है।

महादेव सट्टा ऐपः रायपुर ईडी दफ्तर में शेफाली बग्गा से हुई पूछताछ

रायपुर, 17 जुलाई (हाईवे चैनल)। राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने मशहूर स्पोर्ट्स एंकर शेफाली बग्गा पर बड़ी कार्रवाई की है। महादेव सट्टा ऐप मामले में पूछताछ के लिए ईडी की टीम उन्हें रायपुर लेकर आई है, जहां उनके रायपुर स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ शुरू हो चुकी है। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, महादेव बेटिंग ऐप को प्रमोट करने में शेफाली बग्गा की संदिग्ध भूमिका रही है, जिसे लेकर ईडी उनसे सघन पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही, ईडी की टीम शेफाली बग्गा के हवाला कारोबारियों के साथ कथित संबंधों और उनके बीच हुए वित्तीय लेनदेन के बारे में भी कड़े सवाल-जवाब कर रही है।

आपको बता दें कि शेफाली बग्गा का नाम कुछ दिनों पहले मशहूर क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ भी जुड़ चुका है, हालांकि दोनों ने ही इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार और गलत बता दिया था। आपकों बता दें की प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन बुक और Skyexchange.com से जुड़े सट्टेबाजी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 91.82 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। इस कार्रवाई के तहत दुबई की दो कंपनियोंपरफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट एलएलसी' और 'एग्जिम जनरल ट्रेडिंग' के खातों में जमा 74.28 करोड़ रुपये से अधिक की राशि फ्रीज की गई है, जो कथित तौर पर सौरभ चंद्राकर, अनिल अग्रवाल और विकास छपरिया के जरिए अवैध पैसे को वैध बनाने में इस्तेमाल हो रही थी।

शिकोहाबाद में बदमाशों ने स्कूल में बच्चों को बनाया बंधक, एसओजी के दो जवानों को लगी गोली

नई दिल्ली, 17 जुलाई (न्यूज चैनल)। फिरोजाबाद में शिकोहाबाद के नगला कन्हई क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग में एसओजी के दो जवान घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए शिकोहाबाद संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। एसओजी के एक जवान की हालत गंभीर है, जिन्हें उपचार के लिए आगरा रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने स्कूल के बाहर घेराबंदी कर रखी है। पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बताया गया है कि इटावा से भागे हुए दो बदमाश सबसे पहले स्वामीनगर पहुंचे। यहां से श्रीराम रिसोर्ट के पास किसी ग्रामीण की बाइक उठाकर भागे। इसके बाद नगला कन्हई के स्कूल में घुस गए। बदमाशों ने स्कूल में बच्चे पकड़ लिए। इसके बाद जब एसओजी की टीम ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने एसओजी टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।

ब्रेकिंग न्यूज

पीएम मोदी बोले- जींद अब बीजेपी-एनडीए के गुड गवर्नेंस का मॉडल

नई दिल्ली, 17 जुलाई (न्यूज चैनल)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि जींद, बीजेपी-एनडीए सरकार के अच्छे शासन (गुड गवर्नेंस) के मॉडल का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में हरियाणा विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ा है। जींद में कई

विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के कार्यक्रम ने बीजेपी सरकार के विकास के एजेंडे को नई गति दी है। मोदी ने कहा कि आज जींद, बीजेपी-एनडीए के अच्छे शासन के मॉडल की मिसाल बन रहा है। पिछले कुछ सालों में पूरा हरियाणा राज्य विकास के नए रास्ते पर चल पड़ा है। आज का कार्यक्रम बीजेपी की डबल इंजन सरकार के इस मिशन में नई ऊर्जा भर रहा है। जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन-पावर्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखाए जाने का ज़िक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मौके ने देश के इतिहास में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने कहा कि आज जींद और हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है; यहीं से देश को अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज भी हम पढ़ते और सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी। उसी तरह, भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का ज़िक्र होगा, तो जींद, सोनीपत और हरियाणा का नाम ज़रूर याद किया जाएगा। इस इलाके से अपने जुड़ाव को याद करते हुए मोदी ने कहा कि जींद की उनकी यात्रा ने उनके संगठनात्मक काम के शुरुआती दिनों की यादें ताज़ा कर दीं।

चूहा- सुनती हो, पुरी में जगन्नाथ यात्रा में भगदड़ हो गई और एक की मौत हो गई।
चुहिया- हां जी, धार्मिक महोत्सव में कई घटनाएं होने के बाद भी लोग सबक नहीं लेते हैं..!

देवपुर के पास भीषण सड़क हादसाः अर्टिगा और बाइक की टक्कर में युवक की मौत, 3 युवतियां घायल

धमतरी 17 जुलाई (हाईवे चैनल)। धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत देवपुर के पास आज शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसा इतना भयावह था कि टक्कर के बाद युवक के दोनों पैर शरीर से अलग हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगरी के देवपुर के पास तेज रफ्तार अर्टिगा कार और मोटरसाइकिल के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक चालक समीर की घटनास्थल पर ही

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मृतक के दोनों पैर कटकर अलग हो गए

मौत हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मृतक के दोनों पैर कटकर अलग हो गए। इस दुर्घटना में तीन युवतियां भी घायल हुई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटनाग्रस्त बाइक और अर्टिगा कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।

12 साल के बालक को मगरमच्छ जिंदा खा गया, जबड़े में दबाया, उछाला और लील गया

नई दिल्ली, 17 जुलाई (न्यूज चैनल)। यूपी के बहराइच में 12 वर्षीय बालक को मगरमच्छ जिंदा खा गया। घटना से घर में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटना का वीडियो सामने आया है। इसमें मगरमच्छ बालक को लीलते हुए दिख रहा है। वीडियो देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। घटना बौंडी थाना के मुरौवा गांव की है। गांव निवासी सुनील सिंह (12) बृहस्पतिवार को अपने चाचा के साथ धान की रोपाई करने खेत गया था। शाम के समय काम खत्म होने के बाद वह घाघरा (सरयू) नदी के किनारे हाथ-

मुंह धोने गया। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे एक मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला कर उसे जबड़ों में दबोच लिया और नदी में खींच ले गया।

मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सुनील को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन मगरमच्छ के हमले के कारण उसे नहीं बचाया जा सका। देर रात करीब 110:30 बजे स्थानीय ग्रामीणों ने नदी से उसका शव बरामद किया। शव के एक पैर और पेट का हिस्सा मगरमच्छ खा गया। मृतक सुनील के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था। वह अपने भाई-बहनों के साथ रह रहा था और क्षेत्र के माधवपुरवा-करेहना विद्यालय में कक्षा छह का छात्र था।

धमतरी में हाईकोर्ट बेंच खुलने से लोगों को मिलेगा सुलभ न्याय, बिलासपुर तक लंबी दूरी का झंझट होगा खत्म

आशीष जैन

धमतरी, 17 जुलाई (हाईवे चैनल)। धमतरी सहित मध्य एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। अधिवक्ताओं, सामाजिक संगठनों और नागरिकों का कहना है कि वर्तमान में किसी भी हाई कोर्ट संबंधी मामले के लिए बिलासपुर जाना पड़ता है, जिससे आम नागरिकों को आर्थिक, मानसिक और समय संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि धमतरी में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की जाती है तो यह न केवल धमतरी जिले, बल्कि आसपास के कई जिलों के लाखों लोगों के लिए न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ और प्रभावी बना सकती है। वर्तमान में धमतरी, कांकेर, गरियाबंद, बालोद, महासमुंद, बस्तर संभाग सहित कई जिलों के पक्षकारों, अधिवक्ताओं और सरकारी अधिकारियों को हर सुनवाई के लिए बिलासपुर तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई मामलों में एक ही तारीख के लिए पूरा दिन यात्रा में निकल जाता है, जिससे अतिरिक्त खर्च और समय की बर्बादी होती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह और भी बड़ी चुनौती बन जाती है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि धमतरी में हाई कोर्ट बेंच स्थापित होने से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। लोगों को समय पर सुनवाई मिल सकेगी, लंबित मामलों के निपटारे में गति आएगी और न्याय तक आम नागरिकों की पहुंच आसान होगी। इससे अधिवक्ताओं को भी स्थानीय स्तर पर बेहतर अवसर मिलेंगे तथा न्यायिक सेवाओं से जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। नागरिकों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विस्तार और विभिन्न क्षेत्रों से बिलासपुर की दूरी को देखते हुए प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि धमतरी अपनी भौगोलिक स्थिति, सड़क संपर्क और आसपास के जिलों से बेहतर कनेक्टिविटी के कारण हाई कोर्ट बेंच के लिए उपयुक्त स्थान हो सकता है।

क्षेत्र के विकास में होगी सहायक

हाई कोर्ट बेंच बनने से क्षेत्र के विकास को भी नई दिशा मिल सकती है। न्यायिक संस्थानों के विस्तार से प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ेंगी, होटल, परिवहन, दस्तावेज़ीकरण, बैंकिंग और अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही धमतरी की पहचान एक महत्वपूर्ण न्यायिक केंद्र के रूप में स्थापित हो सकती है।

धमतरी न्यायालय में है पर्याप्त जगह

बता दें कि धमतरी जिला न्यायालय प्रदेश के बड़े न्यायालयों में से एक है। यहाँ यदि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाती है तो यहाँ जगह की कमी नहीं होगी। जबकि प्रदेश के कई जिला न्यायालयों में जगह व कमरों की

- धमतरी, कांकेर, बालोद, गरियाबंद सहित बस्तर संभाग के सभी जिलों के पक्षकारों, अधिवक्ताओं और अधिकारियों को हर सुनवाई हेतु नहीं लगानी पड़ेगी बिलासपुर की दौड़
- आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर लोगों द्वारा की जा रही है धमतरी में हाईकोर्ट बेंच खोलने की मांग

कमी वर्तमान में भी है, ऐसे में धमतरी में उच्च न्यायालय बेंच स्थापना के लिए जगह रोड़ा नहीं बन पाएगा। बस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए।

हाईकोर्ट बेंच स्थापना से धमतरी, बस्तर संभाग सहित आसपास के कई जिलों के लोगों को मिलेगा लाभः अधिवक्ता संघ अध्यक्ष नीरजधर तिवारी

हाईवे चैनल से चर्चा करते हुए जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष नीरजधर तिवारी ने कहा कि धमतरी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। पूर्व में कई बार मांग की जा चुकी है और भविष्य में भी विशेष अवसरों पर विशेष तरीके से मांग की जाएगी। धमतरी पहुंचने वाले वरिष्ठ जजो को भी इस संबंध में अवगत कराया जाता है। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना धमतरी में होने से, न सिर्फ धमतरी बल्कि पूरा बस्तर संभाग व आस-पास के कई जिले जैसे बालोद, गरियाबंद, महासमुंद दुर्ग आदि के लाखों निवासियों को इसका लाभ होगा। दूरी घटने से समय व पैसों की बचत होगी। गरीब व मध्यमवर्गीय लोगों के लिये न्याय की प्रक्रिया आसान व सस्ती हो पायेगी। धमतरी जिला न्यायालय में बेंच स्थापना के लिये पर्याप्त जगह व अधोसंरचना है। जिला कोर्ट का निर्माण भविष्य को ध्यान में रख कर बनाया गया है।

अभी हाईकोर्ट का कोरम ही पूरा नहीं है ऐसे में वर्तमान में बेंच की स्थापना संभव नहीं हैः शत्रुहन सिंह साहू

हाईवे चैनल से चर्चा के दौरान राज्य विधिज्ञ परिषद, छत्तीसगढ़ के सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता शत्रुहन सिंह साहू ने बताया कि वर्तमान में धमतरी में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की आवश्यकता तो है लेकिन यह वर्तमान में संभव नहीं है क्योंकि बेंच स्थापना के पूर्व हाईकोर्ट का कोरम (पर्याप्त जजों की संख्या) पूरा होना चाहिये। वह ही अभी पूरा नहीं है। ऐसे में जब तक हाईकोर्ट का कोरम पूरा नहीं हो जाता, बेंच की स्थापना नियमानुसार संभव नहीं है। लेकिन उम्मीद है आगामी कुछ सालों में कोरम पूरा होते ही धमतरी में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग प्रमुखता से की जायेगी। धमतरी में हाईकोर्ट बेंच स्थापना पर निश्चित ही धमतरी-बस्तर सहित आसपास के सभी जिलों के लोगो को इसका लाभ मिलेगा।

हाई कोर्ट बेंच बनने के प्रमुख लाभ

:- आम नागरिकों को सुलभ और त्वरित न्याय मिलेगा।
:- बिलासपुर तक बार-बार यात्रा करने की आवश्यकता कम होगी।
:- समय और आर्थिक खर्च में बड़ी बचत होगी।
:- लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे में मदद मिलेगी।
:- अधिवक्ताओं और न्यायिक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
:- धमतरी और आसपास के जिलों का प्रशासनिक एवं आर्थिक विकास तेज होगा।

CMYK